ग्रामसभा से लोकसभा तक समर्थन अभियान

ग्रामसभा सहमति-पत्र

कालाधन, भ्रष्टाचार व व्यवस्था परिवर्तन के आन्दोलन को समर्थन के सन्दर्भ में

1. भारत स्वाभिमान आंदोलन की कालेधन को वापस लाने व आगे से कालाधन जमा न हो, इसकी सातों प्रक्रियाओं, भ्रष्टाचार से मुक्ति के तीन उपायों व व्यवस्था परिवर्तन के मुख्य छ मुद्दों पर मैं सहमत हूँ।

2. विदेशी पूंजी निवेश यानि F.D.I. के नाम पर जो धन देश में आया है, उसमें भी कालाधन है। F.D.I. में पूरा धन काला ही है ऐसे हम नहीं मानते। अतः F.D.I. में जो वैध धन है उसको लेकर हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु अभी F.D.I. के जरिये आ रही पूँजी के मूल स्त्रोत व कम्पनियों के वास्तविक शेयर होल्डर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। केवल कम्पनी के डायरेक्टर्स व मैनेजर्स के बारे में जानकारी होती है और अक्सर ये उन कम्पनियों के वास्तविक मालिक नहीं होते हैं। F.D.I. से आया धन- काला है या सफेद, इसका पता लगाने के लिए उस धन के मूल स्त्रोत व वास्तविक मालिकों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का कानूनी प्रावधान सरकार को तुरन्त करना चाहिए। इससे एक तो कालाधन जमा करने वाले अधिकांश लोगों का प्रामाणिक रूप से पता लग सकेगा और इन्हीं लोगों का देश व विदेश में F.D.I. के अतिरिक्त जो अन्य अवैध धन व अवैध सम्पत्ति - गोल्ड, माइनिंग, लैंड एंड इन्फ्रॉस्ट्रक्चर, ड्रग्स, कालाबाजारी-वायदा आदि तथा राजनीति से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में देश के भीतर व विदेशों में भी बहुत बड़ी मात्रा में जो कालाधन है - उसका भी पता लगाना आसान होगा व देश को कालाधन मिलने का रास्ता खुलेगा। साथ ही देश में आर्थिक पारदर्शिता भी आयेगी। F.D.I. कालाधन की चाबी या केन्द्र बिन्दु है। इससे देश विदेशों में जमा कालाधन के खजाने के राज़ खुलेंगे।

3. कालाधन देश को मिलने से प्रत्येक ग्राम-सभा या ग्राम-पंचायत को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 100 से 200 करोड़ रुपये विकास के लिए मिलेगा। इससे गाँव के किसानों के खेतों को पूरा पानी व बिजली आदि सभी बुनियादी सुविधाएं व व्यवस्थाएं सुलभ हो सकेंगी। गाँव के बच्चों के लिए विश्वस्तरीय स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालय बन सकेंगे। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। दलित, वाल्मीकि, आदिवासी तथा गरीब - हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख व इसाई आदि किसी भी जाति व मजहब के लोग गरीब व लाचार नहीं रहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

   हमारी सभी क्षेत्रों में जी.डी.पी तथा ग्रोथ-रेट बढ़ेगी। निर्यात बढ़ेगा। रुपये का अवमूल्यन नहीं होगा। पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा (साख) बढ़ेगी। हमारी सैन्य शक्ति मजबूत होगी। क्योंकि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत वहाँ की अर्थव्यवस्था ही होती है। अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द पूरा देश चलता है। देशी विदेशी कर्ज बहुत लिया जा चुका है। टैक्स-मनी से भी देश के बुनियादी विकास के लिए पूरी

पूंजी नहीं मिल पा रही है। अतः अब तो एकमात्र उपाय बचा है कि कालाधन देश को मिलना ही चाहिए। कालाधन वापस आने से भारत दुबारा सोने की चिड़िया बनेगा। अमरीका व चीन के स्थान पर हम सुपर-पावर होंगे। Shining India व Burning India अर्थात् अमीर व गरीब भारत का भेद खत्म होगा।

यह देश मात्र केन्द्र सरकार, सांसदों व राजनैतिक दलों का ही नहीं है, अपितु हम सब नागरिकों या जनता का भी है। अतः आज जबकि पूरा देश एक गम्भीर आर्थिक संकट, गरीबी, मंहगाई व अन्य सामाजिक विषमताओं एवं समस्याओं के दौर से गुजर रहा हो, तब हम सब ग्रामवासी व भारतवासियों का यह कर्तव्य है कि देश की तरक्की, खुशहाली या विकास के लिए लगभग 400 लाख करोड़ रुपये का कालाधन देश को दिलाने के लिए मिलकर संघर्ष करें व संगठित होकर आवाज उठायें व राष्ट्रहित में इस मुहिम का समर्थन करें।

लोकतन्त्र में ''लोक'' अर्थात् ''जनता'' सर्वोपरि होती है। देश की सभी लगभग- 2 लाख 39 हजार 867 ग्राम सभायें; 6 लाख 38 हजार 365 गाँव; देश की 121 करोड़ जनता, सभी ईमानदार सांसद व राजनैतिक दल जब कालाधन देश को दिलाने के लिए एकमत हैं, तो केन्द्र सरकार को कालेधन पर भारत स्वाभिमान के द्वारा सुझाये गये सभी सात प्रक्रियों पर तुरन्त कार्रवाई करनी ही चाहिये।

विशेष टिप्पणी :.....

.....

.....

.....

ग्रामसभा का नाम : ....., जिला : .....

खण्ड व तहसील : ....., राज्य : .....

सम्पर्क संख्या : ....., दिनांक : .....

ग्रामसभा प्रधान का नाम व हस्ताक्षर :

ग्रामसभा सदस्यों का नाम व हस्ताक्षर :

ग्रामसभा की मुहर